दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, बुधवार 04 मार्च 2020 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 156

महत्वपूर्ण एवं खास

सरकार ने एपीआई से तैयार नुस्खों की निर्यात नीति में संशोधन किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। सरकार ने सक्रिय औषधि अवयव (एपीआई) और उनके द्वारा तैयार नुस्खों के सम्बंध में निर्यात नीति तथा प्रतिबंधित निर्यात में संशोधन किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रतिबंध फौरन प्रभाव में आ जायेंगे और अगले आदेशों तक लागू रहेंगे।

हिंसा के दौरान पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाला शाहरुख पकड़ाया

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हिंसा के समय पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानने वाले शाहरुख को दबोच लिया गया है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम ने सोमवार देर रात शाहरुख को उत्तर प्रदेश के बरेली से गिरफ्तार किया है। दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख ने आठ राउंड गोलियां भी चलाई थी। दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। साथ ही उसको पनाह देने वाले लोगों की तलाश शुरू हो गई है। आपको बताते जाए कि दिल्ली हिंसा के दौरान 24 फरवरी को जाफराबाद इलाके में शाहरुख ने 8 राउंड फायरिंग की थी। इस शख्स ने फायरिंग के दौरान एक पुलिस कर्मी पर पिस्टल भी तान दिया था। फायरिंग करते हुए यह शख्स फिर भीड़ में गायब हो गया था।

आगरा में कोरोना के 6 संदिग्ध मिले

नईदिल्ली (आरएनएस)। आगरा में नमूने की जांच के दौरान हाई वायरल के छह मामलों की जानकारी मिली है। ये वह लोग हैं जो कल नई दिल्ली में सीओवीआईडी-19 मरीजों के संपर्क में आए हैं। इन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। इनके नमूनों को एनआईवी, पुणे पुष्टि के लिए भेजा गया है। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम (आईडीएसपी) नेटवर्क के जरिये उन लोगों का पता लगाया जा रहा है जिनके संपर्क में ये छह लोग आए।

दिल्ली हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने फूंके 122 घर, 322 दुकानें भी तबाह

नईदिल्ली (आरएनएस)। उत्तर-पूर्वी जिला प्रशासन ने दिल्ली में पिछले सप्ताह हुई हिंसा में हुए नुकसान को लेकर अंतरिम रिपोर्ट तैयार कर ली है. इसके मुताबिक, हिंसा में उपद्रवियों ने 122 घरों को जला दिया. उत्तर-पूर्वी दिल्ली जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सप्ताह हिंसा के दौरान कम से कम 122 घर, 322 दुकानें और 301 वाहन पूरी तरह से खाक हो गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हालांकि, माना जा रहा है कि अंतिम रिपोर्ट में यह संख्या और बढ़ सकती है.वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि रविवार सुबह तक एसडीएम के नेतृत्व में 18 टीमों की ओर से शेयर किए गए इनपुट के आधार पर यह डाटा तैयार किया गया. सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देशों के बाद यह टीम उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा प्रभावित इलाकों में क्षति का आकलन कर रही है. बता दें कि हिंसा में अब तक 40 से ज्यादा लोगों के मरने और 350 से अधिक लोगों के घायल होने का दावा किया गया है। हिंसा के संबंध में 1300 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में स्थिति शांत है और पिछले पांच दिनों में हिंसा का कोई मामला सामने नहीं आया है।

मोदी ने लिया कोरोना से निपटने की तैयारी का जायजा

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 नोवेल कोरोनावायरस से निपटने की तैयारी का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 नोवेल कोरोनावायरस के मद्देनजर तैयारी की गहन समीक्षा की। भारत आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग से लेकर तुरंत चिकित्सा प्रदान करने तक की समस्त गतिविधियों के लिए विभिन्न मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं।

स्टैंड अप इंडिया योजना में 81 प्रतिशत से अधिक महिलाएं खाताधारक

» मुद्रा ऋण लेने वालों में 70 प्रतिशत महिलाएं

नईदिल्ली (आरएनएस)। वित्त मंत्रालय ने पिछले छह वर्षों में विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं जिनमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान हैं। इन योजनाओं ने महिलाओं को बेहतर जीवन जीने और उद्यमी बनने के उनके सपनों को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है।

जैसा कि हम 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, हम वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं पर नज़र डालते हैं जिन्होंने भारत में महिलाओं को लाभान्वित किया है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना - आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन के लिए जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। यह योजना में संस्थागत ऋण संरचना का लाभ उठाने का प्रयास किया गया है ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों जैसे अपर्याप्त सुविधा प्राप्त लोगों तक पहुंचाया जा सके ताकि वे राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में भाग ले सकें।

इस योजना का उद्देश्य कम से कम अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के एक तथा एक ग्रीनफ़ील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए एससीबी की प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है।

स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 17.02.2020 तक, 81 प्रतिशत से अधिक खाताधारकों में से 73,155 खाते महिलाओं के लिए खोले गए हैं। महिला खाताधारकों के लिए 16712.72 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। महिला खाताधारकों को 9106.13 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)- गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल, 2015 को पीएमएमवाई की शुरुआत की गई थी। इन ऋणों को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंकों, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए जाते हैं।

7896 करोड़ के नकली चालान के बड़े रैकेट का भंडाफोड़

» दो अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय कर के वंचन रोधी स्कंध, दिल्ली पश्चिम आयुक्तालय के अधिकारियों ने 23 शेल कंपनियों के नेटवर्क के इस्तेमाल द्वारा 1709 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी)सहित 7896 करोड़ रुपये के नकली चालान के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें खरीद और माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना चालान तैयार किया जाता था। इस मामले में 29 फरवरी, 2020 को दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी व्यक्ति फर्जी चालान के आधार पर आईटीसी को पारित करने के उद्देश्य से कई फर्जी कंपनी बनाकर कर की चोरी कर रहे थे। आईटीसी को वास्तविक बनाने के लिए उन्होंने बैंकिंग लेनदेन का भी इस्तेमाल किया। इन फर्मों ने खरीदारों को फर्जी चालान जारी किया, जिन्होंने वास्तव में किसी भी सामान को प्राप्त किए बिना धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया और जीएसटी देयता के लिए अयोग्य आईटीसी का लाभ उठाकर सरकारी खजाने को धोखा दिया। वे कई मोबाइल फोन, कंप्यूटर और गलत दस्तावेजों के साथ अपने ठिकाने में पकड़े गए। आरोपियों ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 (1) (बी) और धारा 132 (1) (सी) के तहत अपराध किए हैं, जो धारा 132 (5) के प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध हैं।

वांछित अपराधी गैंगस्टर गोगी तीन साथियों के साथ गिरफ्तार

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने दिल्ली के सबसे वांछित अपराधी गैंगस्टर गोगी और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि स्पेशल सेल की टीम ने चार लाख के इनामी बदमाश जितेंद्र मान उर्फ गोगी, कुलदीप मान उर्फ फज्जा, रोहित उर्फ मोई तथा कपिल उर्फ गौरव को गिरफ्तार किया है। गोगी पर दिल्ली में चार लाख और हरियाणा में ढाई लाख का इनाम घोषित था। हरियाणा पुलिस ने ये इनाम हर्षिता दहिया हत्या के बाद रखा था। कुलदीप और मोई पर दो लाख का इनाम घोषित था। उन्होंने कहा कि बदमाशों के पास से छह पिस्तौल के अलावा गोलाबारूद जब्त किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की माने तो यह गैंग दिल्ली के कई गैंगवार में शामिल रहा है।

सरकार ने 4 साल में महिलाओं को दिया 16,712 करोड़ का ऋण

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि देश में महिलाओं को 'स्टैंड अप इंडिया' योजना के तहत करीब चार साल में 16,712 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर किया गया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि स्टैंड अप इंडिया योजना के लाभार्थियों में 81 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है। स्टैंड अप इंडिया लोन योजना से एक अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति या फिर एक महिला को बैंक से लोन लेकर एक नई परियोजना या व्यवसाय की स्थापना करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन देता है। पिछले छह साल के दौरान मंत्रालय ने विभिन्न योजनाएं पेश की हैं जिनमें महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विशेष प्रावधान हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले बयान में मंत्रालय ने कहा कि इन योजनाओं से महिलाएं वित्तीय रूप से सशक्त हुई हैं और वे बेहतर जीवन जीने के साथ उद्यमिता के अपने सपने को साकार कर पा रही हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत पांच अप्रैल, 2016 को हुई थी।

विपक्षी सांसदों के नारेबाजी पर लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला ने दी हिदायत

नईदिल्ली (आरएनएस)। बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में दिल्ली हिंसा को लेकर हंगामा मचता रहा। लोकसभा में दिल्ली हिंसा को लेकर हंगामा कार्यवाही शुरू होने के साथ ही प्रारंभ हो गया। कांग्रेस सांसदों ने नारेबाजी करना प्रारंभ कर दिया। सांसदों के हंगामे को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला काफी नाराज हो गए। स्पीकर ने सांसदों को वेल में नहीं आने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला ने आगे कहा कि वे सांसदों को सदन में प्लेकार्ड और पोस्टर नहीं लाने देंगे। विपक्ष ये साफ करे कि क्या वे प्लेकार्ड के साथ सदन में आना चाहते हैं, आप अगर प्लेकार्ड के साथ संसद चलाना चाहते हैं तो आप घोषणा करिए, आप कहिए कि प्लेकार्ड लेकर संसद में आना चाहते हैं, मैं इजाजत दूंगा।

लोकसभा अध्यक्ष ने सोमवार को हुई धक्का-मुक्की का हवाला देते हुए कहा कि क्या आप सदन को ऐसे ही चलाना चाहते हैं। वहीं, विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहे, जिसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि दिल्ली में लाशों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस विषय को उठाने का अधिकार हमें है, हम आपसे (लोकसभा अध्यक्ष) गुजारिश करते हैं, आप इसपर चर्चा कराएं और सरकार चर्चा से भाग रही है।

देश भर में शुरु हुआ जन औषधि सप्ताह

नईदिल्ली (आरएनएस)। देश भर में एक से सात मार्च 2020 तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर, जन औषधि परिचर्चा और जन औषधि का साथ जैसी विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

सप्ताह के दौरान जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से देश भर में रक्त चाप, मधुमेह की जांच, डाक्टरों द्वारा निशुल्क चिकित्सा जांच और दवाओं का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविरों में आने वाले लोगों को जन औषधि केन्द्रों में बेची जा रही रही दवाओं की गुणवत्ता और उनकी कीमतों के फायदे के बारे में जानकारी दी जा रही है।

जन औषधि सप्ताह के दूसरे दिन कल आईएमए चैप्टर के प्रमुख सिटी डाक्टरों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक कंटीन्यूएस मेडिकल एजुकेशन- सीएमई कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जन औषधि केन्द्रों से मिलने वाली दवाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। डाक्टरों से कहा गया कि वे अन्य डाक्टरों को भी जन औषधि केन्द्रों की दवाओं के महत्व के बारे में समझाएं और मरीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसी दवाएं लिखें।

' प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना' भारत सरकार के औषध निर्माण विभाग की एक महती परियोजना है जो सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराने के अपने प्रयासों से बड़े स्तर पर आम जनता को लाभ पहुंचा रही है। इस समय देश में ऐसे औषधि केन्द्रों की संख्या बढ़कर 6200 से ज्यादा हो चुकी है।

17 राज्यों के 82 दिव्यांग कारीगर 'एकम फेस्ट' में शामिल

नईदिल्ली (आरएनएस)। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त विकास निगम (एनएचएफडीसी) द्वारा स्टेट एम्पोरिया कॉम्प्लेक्स, बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-1 में एक सप्ताह तक चलने वाले प्रदर्शनी-सह-मेला - एकम फेस्ट में 17 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 82 दिव्यांग कारीगर और उद्यमी अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इनमें 44 पुरुष और 38 महिला दिव्यांग कारीगर और उद्यमी शामिल हैं। 'एकम फेस्ट' 2 मार्च से 9 मार्च, 2020 तक 11 बजे सुबह से 9 बजे रात तक लोगों के लिए खुला रहता है। इसमें दिव्यांग कलाकारों और प्रसिद्ध पेशेवरों द्वारा प्रदर्शन सहित कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। दिव्यांग पेशेवरों द्वारा ज्योतिषीय परामर्श और पैर की मालिश इस आयोजन के अन्य आकर्षण हैं।

'एकम फेस्ट' में जम्मू-कश्मीर से पुदुचेरी और नगालैंड से गुजरात तक, देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों को आमंत्रित किया गया है। फेस्ट में जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के उत्पादों, हस्तकला, हथकरघा, कढ़ाई के काम और ड्राई फ्रूट्स के उत्पादों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। मेले के दौरान 17 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लगभग 82 दिव्यांग उद्यमी/कारीगर तथा संगठन अपने सुंदर उत्पादों, सेवाओं और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं।

'एकम फेस्ट' स्टॉल में कई श्रेणियों में होम डेकोर और लाइफस्टाइल, कपड़ा; स्टेशनरी और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों; पैक खाद्य और जैविक उत्पाद; खिलौने और उपहार; और पर्सनल ऐक्सेसरी - जवेलरी, क्लच बैग्स आदि जैसे व्यापक उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी की उपस्थिति में कल शाम फेस्ट का उद्घाटन किया गया। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और रतन लाल कटारिया भी उपस्थित थे।

पाक के सीजफायर का भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जबाव

पुंछ (आरएनएस)। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर पाक ने सीजफायर का उल्लंघन किया है और पुंछ जिले में सीमा पार से गोलीबारी की। मनकोट और मेंढर सेक्टर में मोर्टार भी दागे गए जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जबाव दिया। पाक आए दिन जम्मू-कश्मीर के में गोलीबारी कर रहा है। वहीं सोमवार तड़के पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुए मोर्टार दागे। बसूनी गांव में एक मकान को नुकसान पहुंचा। सोमवार को भी आधी रात पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर के मनियारी इलाके में गोलाबारी शुरू कर दी। बता दें कि पिछले दिनों सुरक्षाबलों ने जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में बिजबेहरा इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुए एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के दो आर्तकियों को ढेर कर दिया था। दोनों आर्तकियों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के गुंडबाबा संगम में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे थे।

संसदीय समिति की सभी बैठकों से नदारद रहे 95 सांसद

» भाजपा से ज्यादा कांग्रेस की रही उपस्थिति

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद के बजट सत्र पर के दौरान राज्यसभा में सभापति एम. वेंकैया नायडू ने संसद की स्थायी समितियों की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति पर चिंता जताई है।

नायडू ने बताया कि 18 मंत्रालयों के आवंटन की समीक्षा करने वाली आठ विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों (डीआरएससी) की किसी भी बैठक में 95 सांसदों ने भाग नहीं लिया। नायडू ने पूरे ब्यौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने तीन सप्ताह के संसदीय अवकाश के दौरान 20 बैठकें कीं। इस समिति में 244 सदस्य (लोकसभा से 166 और राज्यसभा से 78) हैं। नायडू ने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (65.5:) समिति की बैठकों में सबसे अधिक उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि सबसे कम उपस्थिति वाणिज्य डीआरएससी (32.3:) में थी। राज्यसभा में बीजेपी 244 में से 110 सांसदों की संख्याबल में हैं जिनमें से 58 प्रतिशत उपस्थित हुए और कांग्रेस के 32 सांसद (62 प्रतिशत) उपस्थित हुए। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गठित अनुदान मांगों की समितियों में से राज्यसभा की आठ समितियों ने 20 बैठकें कीं। 63 घंटे तक चली इन बैठकों में 18 मंत्रालयों की मांगों पर विचार किया गया। यह सदन की 10 बैठकों के बराबर थी।

सीएए का विरोध करने वाले 5 विदेशियों को सुनाया भारत छोड़ने का फरमान

नई दिल्ली (आरएनएस)। एक तरफ संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर विरोध-प्रदर्शन जारी है, वहीं केंद्र सरकार ने भी कई मौकों पर यह साफ-साफ बता दिया है कि वह इसे वापस नहीं लेगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाली इस कानून के विरोध में कई विदेशी भी सामने आए।

ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने इसे वीजा नियमों का उल्लंघन माना और ऐसे 5 विदेशियों को देश छोड़ने के लिए कहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक पांच विदेशी नागरिक सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। यह वीजा नियमों का उल्लंघन है। इन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने सीएए पर सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। जिनेवा में भारत के स्थाई दूतावास को इसकी जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि सीएए भारत का आंतरिक मामला है। और यह कानून बनाने वाली भारतीय संसद के संप्रभुता के अधिकार से संबंधित है।